

तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सितार है।
यह तुम्हारे हाथ की बात है कि तुम उससे
मधुर स्वर झंकूत करो या बेसुरी आवाजें
निकालो -खलील जिब्रान

कानून के हिसाब

यकीनन यह खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में साफ किया है कि पुश्तैनी संपत्ति में बेटियों को हक सिर्फ़ 2005 में संशोधित कानून की अवधि के बाद ही नहीं मिलेगा, बल्कि पिछले दावे भी इसी कानून के हिसाब से तय होंगे। यानी उन्हें अपने हक के लिए किसी तारीख पर निर्भर नहीं रहना होगा। हमारे समाज में बेटियों को संपत्ति के हक से वर्चित करने की परंपराएं ही नहीं, दलीलें भी दी जाती रही हैं। कई लोग पुश्तैनी संपत्ति में हक के बदले स्त्री-धन की परंपरा का हवाला देते हैं लेकिन उसमें दो पेच हैं। एक तो पुरुष-सत्ता वाले समाज में उस पर पति या परिवार का प्रत्यक्ष या परोक्ष अधिकार हो जाता है। दूसरे, वह पुश्तैनी संपत्तियों जितनी सुरक्षा प्रदान करने में पर्याप्त नहीं होता। पिर बेटियों को हर मामले में बेटों के बराबर अधिकार होने से स्त्री-पुरुष समानता के अलावा समाज में बेटों के प्रति मोह भी कुछ घटेगा। लिहाजा, इससे पुरुष वर्चस्व वाली व्यवस्था की बुनियाद भी हिलेगी। हाल में बेटों के प्रति मोह का एक उदाहरण इस साल के आर्थिक संवेदक्षण में उभर कर सामने आया। हालांकि इसका एक सुखद पहलू स्त्री जनसंख्या में कुछ बढ़ोतारी के रूप में सामने आया, जो घटते स्त्री-पुरुष अनुपात और कन्या भरण हत्या के दौर में वाकई शुभ कहा जाएगा। आर्थिक संवेदक्षण बताता है कि बेटों की चाह में बेटियों की आबादी 2.1 करोड़ ज्यादा हो गई। बेटियों की जनसंख्या के मामले में यकीनन यह खुशखबरी है और इससे स्त्री-पुरुष अनुपात कुछ बेहतर भी हुआ है। लेकिन असली सवाल मानसिकता का है या कहिए उससे भी बढ़कर समाज में पुरुष वर्चस्व का है। यह तभी टूटेगा जब स्त्रियों को संपत्ति में पूरा अधिकार हासिल होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मायने में क्रांतिकारी फैसला सुनाया है, जिससे हमारे समाज का रंग-ढांग कुछ बदल सकता है। ऐसी ही बुनियादी नुक्ते बदलाव का वॉयस बनते हैं। इसका असर “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसे अभियानों से ज्यादा होता है। इसलिए सरकार अगर स्त्रियों के लिए और सकारात्मक कानूनी रियायतें देने का कदम उठाए तो उसका ज्यादा असर होगा। संसद और विधायिकाओं में एक-तिहाई महिला आरक्षण विधेयक अभी लटका पड़ा है। यूपीए सरकार के दौरान यह विधेयक लोक सभा में अटक गया था। खासकर पिछड़े वर्गे के नेताओं ने कुछ आशंकाएं जाहिर की थीं। सरकार को चाहिए कि सर्वानुमति बनाकर स्त्रियों का यह वाजिब हक उन्हें दिलाए।

ट्राफी पर कछा

दह महीने की हाड़तोड़ मेहनत आखिरकार रंग लाई। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने चौथी बार ट्राफी पर कब्जा जमाकर क्रिकेट को धर्म मानने वाले देश में लोगों को बेइंतहा खुशियां बांटने का मौका दिया। कोच राहुल द्रविड़ और आठ सदस्यीय सपोर्ट स्टाफ़ के लिए इससे बेहतरीन, यादगार और खुशनुमा पल नहीं होगा। यह हर किसी के लिए सपने सच होन जैसा है। युवा टीम ने जिस तरह से न्यूजीलैंड की तेज पिच पर तीन बार की चैंपियन आस्ट्रेलिया को छह विकेट से रौंद दिया, वह काबिले तारीफ है। खास बात है टीम हनक के साथ पूरे टूर्नामेंट में नजर आई। इसके आसपास कोई भी टीम नहीं थी। यह दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए आने वाला कल उम्मीदों से भरा है। टीम के सभी खिलाड़ी गजब के प्रतिभाशाली हैं और इसका सारा श्रेय उस गुरु को जाता है, जिन्होंने न केवल इन बच्चों को खेल की बारीकियां बताईं वरन् उन्हें जिंदगी के हर अच्छे-बुरे पाठ को भी खूबसूरती के साथ समझाया। साथ ही बच्चों को अनुशासित रहने और लक्ष्य से ध्यान न भटकाने का गुरुमंत्र भी दिया। मगर कोच की कही एक बात वाकई गौर करने वाली है। जीत के बाद द्रविड़ ने कहा कि, उन्हें भरोसा है कि विश्व कप की यह जीत सिर्फ़ यादें बनकर नहीं रहेंगी बल्कि इन खिलाड़ियों को आगे और भी संघर्ष करना पड़ेगा।' साफ-साफ समझा जा सकता है द्रविड़ का आशय क्या है? सफलता, पैसा और चकाचौंध ने पहले भी कई खिलाड़ियों के स्वर्णिम कॉरियर को तबाह किया है। लिहाजा, सबसे बड़ा सबक यही है कि मर्यादित और अनुशासित रहकर ही लक्ष्य को साधा जा सकता है। इन लोगों को लंबा रास्ता तय करना है। क्रिकेट की दुनिया में बादशाहत बनानी है तो तुरंत के लाभ को छोड़ने की प्रवृत्ति त्यागनी होगी। अतीत में भी जिसने इसे याद रखा, सफलता ने उसी के कदम चूमे। फिलहाल तो जीत के जश्न में खो जाने का वक्त है। दबंग प्रदर्शन से इनके कंधों पर जिम्मदारियों का भी बोझ है। चुनांचे इन्हें उस दबाव तते नहीं आना होगा। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि इनमें से कितने अगले रांगड़ में पहुंच पाते हैं।

सत्संग

परमात्मा परमेश्वर

जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं अतएव उनके विचार से परमात्मा और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कायरे को भोगता है लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता। अपितु वह साक्षी, अनुमतिदाता और परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा और परमात्मा भिन्न-भिन्न हैं। परमात्मा के हाथ-पैर सर्वत्र रहते हैं लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं होता है। चूंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतएव वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत हैं और भगवान उन सबमें भिन्न रूप में निवास करता है। तय यह है कि प्रत्येक जीवन परमेश्वर का नित्य अंश है। और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठतापूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रतापूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चूंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है अतएव वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सकें। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ढुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर और भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवद्गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से जीव को यह विस दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के अनुकूल नहीं हैं।

“ऑपरेशन ऑलआउट”

ऐसा होता है तो निश्चय ही जम्मू-कश्मीर के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आरिंग सेना के जवानों पर मुकदमा दर्ज की जौबत क्यों आई और क्या यह सही कदम है? आरोप लगाया गया है कि सेना की गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। इसके

अनुसार सेना की कार्रवाई से कुछ और लोगों की मौत हो सकती थी लेकिन वे संयोग से बच गए। वैसे इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। घटना शोपियां जिले के गावं गनोवपोरा का है। सेना का काफिला वहां से गुजर रहा था। दरअसल, काफिला बड़ा था जिसमें से पांच गाड़ियां पीछे छूट गई थीं। उस पर लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए।

आरंभ में संख्या कम थी लेकिन धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी

सतीश पेडणोकर



हर भारतवासी को चिंतित करेगी कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने वहां कार्रवाई कर रहे सेना के जवानों पर मुकदमा दर्ज किया है। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वे जवान 10 गढ़वाल यूनिट के हैं और इनमें एक मेजर स्तर का अधिकारी भी शामिल है। मुकदमा 302 यानी हत्या और 307 यानी हत्या के प्रयास के तथा 336 यानी जिंदगी को खतरे में डालने वाले के तहत दर्ज हुआ है। पिछले काफी समय से जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के बीच गजब किस्म का समन्वय देखा जा रहा था। कश्मीर में शांति की कामना करने वाले हर व्यक्ति की चाहत है कि यह समन्वय बना रहे और राज्य के अंदर के आतंकवादी और सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले परास्त हों। आपसी समन्वय के कारण ही 2017 में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली और 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। कई युवा आतंकवादी बनने के बाद आम जिंदगी में लौटे हैं। इस एक घटना ने समन्वय की स्थिति पर गहरा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। यह प्रश्न उठने लगा है कि सुरक्षा एजेंसियां आपसी तालमेल से जो “ऑपरेशन ऑलआउट” चला रहीं हैं उनका क्या होगा? क्या पुलिस और सेना के बीच ऐसे किसी प्रकार के टकराव के दौर की शुरुआत होगी और आतंकवादी एवं अलगाववादी इसका लाभ उठाएंगे? ऐसा होता है तो निश्चय ही जम्मू-कश्मीर के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आखिर सेना के जवानों पर मुकदमा दर्ज की नौबत क्यों आई और क्या यह सही कदम है?

आरोप लगाया गया है कि सेना की गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। इसके अनुसार सेना की कार्रवाई से कुछ और लोगों की मौत हो सकती थी लेकिन वे संयोग से बच गए। वैसे इस घटना की न्यायिक जांच के अदेश भी दे दिए गए हैं। घटना शोपियां जिले के गावं गनोवपोरा का है। सेना का काफिला वहां से गुजर रहा था। दरअसल, काफिला बड़ा था जिसमें से पांच गढ़ियां पीछे छूट गई थीं। उस पर लोगों ने पथर फेंकने शुरू कर दिए। आरंभ में संख्या कम थी लेकिन धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई न देख वे पूरी तरह हमलावर हो गए थे।

एक जवान को उन्होंने खींच लिया और उस पर हमला कर दिया। जो कुछ दृश्य दिख रहा है, उसमें साफ है कि सेना ने कार्रवाई न की होती तो पत्थरबाज उड़े पीट-पीटकर मार डालते। अब सेना के पास दो ही विकल्प था; या तो अपने साथी को उन पत्थरबाजों के हाथों मरता छोड़कर भाग जाती या उसे बचाने के लिए कार्रवाई करती। इनके लिए भागना भी आसान नहीं था। कोई भी यह स्वीकार करेगा कि एक विकल्पित पैदा हो गई थी, जिसमें सेना को कार्रवाई करनी पड़ी। जो कोई भी सेना के जवानों को दोष देता है, उनसे पूछा जाना चाहिए।

कि उनकी जगह आप होते तो क्या करते ? सेना के खिलाफ़ इनका गुस्सा किस कारण था ? कुछ दिन पहले उसी गांव में एक आतंकवादी छिपा हुआ था, जिसे सेना ने मुठभेड़ में मार दिया था । अगर आतंकवादियों के पक्ष में किसी की हमदर्दी है और वह पत्थरों और डंडों से सेना के काफिले पर हमले के रूप में निकालेगा तो फिर उसका जवाब देना पड़ेगा । मौत किसी का हो, दुख तो होगा । किंतु लोगों को सोचना चाहिए कि आप सेना पर हमला करने आएंगे तो जवाब में आपको फूल नहीं मिलेगा । दुर्भाग्य देखिए, प्रदेश की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती तक ने सेना की कार्रवाई की तीखी आलोचना कर दी । ऐसा ही आचरण उमर अब्दुल्ला का है । ऐसा भी नहीं है कि लोगों के हमले में सेना को क्षति नहीं पहुंची । हिंसक भीड़ के हमले में एक जेसीओ (जूनियर कमीशंड ऑफिसर) समेत सात सैन्यकर्मी घायल हो गए थे । अलगाववादियों को तो बहाना चाहिए । उन्होंने बंद का आह्वान कर दिया । किंतु महबूबा मुफ्ती प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं । व्या उहें नहीं पता कि 2017 में आतंकवादियों से जूझते हुए

88 जवान शहीद हुए हैं ? इस वर्ष ही 4 जनवरी और तीन बर्फबारी में । सेना के जवानों के बारे में क्या ? महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी भी प्रदेश से सशस्त्र बल विशेषाधिकार के पक्षधर हैं । नेशनल कॉर्प्रेस भी इसकी मतलब चाहती है कि ऐसे आधार बन जाए, जिनसे बना सकें । हम यहां अप्स्ट्रा के बहस में नहीं ऐसी खबर आई है, जिसमें कहा गया था कि सरल और नरम बनाने पर विचार कर रही राष्ट्रवाद ने इससे इनकार किया है । हमें यह सुना

गान लड़ते शहोद हो चुक हैं
लिदान को कोई भूल सकता
पीड़ीपी सरकार में होते हुए
ननून यानी अफस्ता हटाने की
गग कर रही है। ये पार्टीयां
वे केंद्र पर इसके लिए दबाव
हीं पढ़ना चाहते। मगर हाल
सरकार अफस्ता को थोड़ा
है। सेनाध्यक्ष जनरल विपिन
नझन होगा कि सुरक्षा बलों
बड़े आतकवादियों के मारे जाने से पत्थरबाजी में कमी आई है। अप्रदेश के पुलिस महानिदेशक ऐसी धारणा रखते हैं तो वे सेना के किंतु टुकड़ी के खिलाफ आसानी से मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होंगे। निश्चय ही इसके पीछे राजनीतिक दबाव होगा। यह दबाव किससे हो सकता है बताने की आवश्यकता नहीं? किंतु देश ऐसे मुकदमे पक्ष में नहीं हो सकता। इस तरह सेना के जवानों के खिलाफ मुद्दल होंगे तो पिछ “ऑपरेशन ऑलआउट” में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाया जा रही है, उसमें बाधा हो जाएगी। उनका मनोबल तोड़ने का काम करेगा। ऐसा हर हाल में नहीं हो सकता।

चलते चलते

दक्षियानूसी का भविष्य

समाज प्रेम संबंधों को पचा नहीं पाता है। प्रेम विवाह के नाम पर उसका कथित स्वाभिमान कुलांचे मारने लगता है। कभी जाति तो कभी मजहब इसके बहाने बनते हैं। इस नापसंदगी की हड़ कई बार प्रेमीयुगल की हत्या पर जा ठहरती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा खासतौर इसके लिए बदनाम रहे हैं, विशेषकर खाप की मानसिकता ऐसे मामलों में ज्यादा दागदार रही है। लेकिन देश का दिल कहे गए दिली, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आकर बसे लोगों का बहुसांस्कृतिक शहर है; यहाँ भी अगर जातीय/धार्मिक कट्टरता प्रेम को अस्वीकार करती है तो उसे किसी क्षेत्र विशेष के सामाजिक पिछड़ेपन पर बोलने का हक बिलकुल नहीं है। आधुनिक सोच वाले युवा अंकित सक्सेना की हत्या-दिलीहों या देश का कोई और भाग, समाज में

इस नापसंदगी की हृत कई बार प्रेमी
युगल की हत्या पर जा ठहरती है। पश्चिमी
उत्तर प्रदेश और हरियाणा खासतौर इसके
लिए बदनाम रहे हैं, विशेषकर खाप की
मानसिकता ऐसे मामलों में ज्यादा दागदार
रही है। लेकिन देश का दिल कहे गए
दिल्ली, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आकर
बसे लोगों का बहुसांस्कृतिक शहर है।
प्रेम करना आज भी कितना मुश्किल है-इसको एक
बार फिर साबित करती है। अंकित का सरेराह कल्पना
तमाम तकनीकी बदलावों और तरकी के बावजूद
हम सोच के स्तर पर कितने पिछड़े हैं यह भी प्रदर्शित
करता है। यह नुशंस वारदात प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा
को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। साथ में
जातीय/धार्मिक तनाव के सबब भी बनते हैं, जिसका
एक लंबा इतिहास रहा है। राजनीति नाम की तीली
समाज के ताने-बाने को जलाकर कर राख करने
को तत्पर रहती है सो अलग। सवाल यह है कि क्या
जो

जोड़ों के भविष्य को दक्यानूसी सोचना समाज पर छोड़ा जा सकता है? दरअसल ऐसे से महिला आंदोलन की मांग रही है जिसका मध्ययुगीन सोच यानी इन्जेट के नाम पर वाली हत्याओं के खिलाफ कड़ा कानून जिसमें राज्य पर अंतर-धार्मिक/जातीय विवाह को पूरा संरक्षण देने की जिम्मेदारी इसको सख्ती और समझदारी से अपलब्ध की जरूरत है। क्योंकि इससे उन युगतिवाचियों की भूमिका बदल जाएगी जो इन डर के साथे ने संबंध की भूमिका कर देते हैं। अंतर-धार्मिक/जातीय प्रेम/विवाह आज भी एक छोटी संपत्र तबके तक ही सीमित है। विभिन्न दरारों द्वारा घोषित तमाम प्रोत्साहन नीतियों की जड़ता को तोड़ने में लगभग असफल है। अंकित जैसों की हत्या हो सकती है। उस पवित्र भाव को नहीं रोका जा सकता। जड़ता की बेंडियां तोड़ने को आतुर हैं।

फोटोग्राफी...



चीन की दीवार
का वो
हिस्सा, जहाँ
हर कोई जाना
चाहता है।

यह फोटो चीन में हेबेंड
प्रांत में उस जगह का है, जहाँ
'चीन की दीवार' दूर तक
फैली है। इसे रोमानि या के
फोटोग्राफ़ ओवी पॉप ने तब
किलक किया, जब वे इस
दीवार का कवरेज करने वहाँ
गए थे। लगातार बर्फ बारी वे
कारण उन्हें वहाँ तक जाने का
मौका नहीं मिल पा रहा था।
फिर एक रात बर्फबारी थम
गई, तो सुबह- सुबह वे इस
जगह पर आ पहुँचे। तब
सूर्योदय हुआ ही था और सूर्य
की किरणें वातावरण खुशनुम
बना रही थीं। उस वक्त बहुत
कम पर्यटक वहाँ पहुँचे थे,
लेकिन पिछले दिनों हुई
बर्फबारी से पर्वत शृंखला का
रंग जरूर बदल गया था।

“डिप्टेरिया”

संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले अब भी जारी हैं। इसलिए बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों में रह रहे लाखों शरणार्थियों के लिए घर लौटना अभी सुरक्षित नहीं है। म्यांमार में समुचित सुरक्षा न अभाव है और सहायता करने वाली ऐजेंसियों, मीडिया और अन्य स्वतंत्र पर्यवेक्षकों पर पाबंदियां जारी हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र की यह चेतावनी रोहिंग्या शरणार्थियों का अपने घर वेच्छा से वापसी के लिए म्यांमार और बांग्लादेश सरकारों के बीच हुए समझौते के दो माह बाद आई है। संयुक्त राष्ट्र दोनों सरकारों पर रोहिंग्या शरणार्थियों के संकट का दीर्घकालिक समाधान हूँढ़ने के लिए जोर दे रहा है। शरणार्थी शिविरों में बाहर लोग आते हैं और रोहिंग्या शरणार्थी की बेटियों को काम देने बदले रकम अदा करने का वायदा करते हैं। यहां आने वाले लघु एक खास आयु की लड़कियों का चयन करते हैं और उनके बां-बाप को हर लड़की के लिए 60 डालर देते हैं। यहां आने वाले पुरुष कहते हैं कि उन्हें 12 से 14 साल की लड़कियां सप्लाइ चाहिए क्योंकि उन्हें घरेलू काम करने में पुरिकल होती है। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल कौष (यूनिसेफ) ने खबरदार किया है कि बांग्लादेश में विस्थापना के बाद लगभग पांच लाख बच्चों की हालत “भयावह” है। आशंका जाताई जा रही है कि उन्हें बच्चों की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। बीमारी, बाढ़, भस्खलन और एक बार पिर से विस्थापन झेलना ड सकता है। “डिथरिया” के तकरीबन चार हजार संदिग्ध अपले सामने आए हैं। ऐसे ही शरणार्थी शिविरों में रह रहे पांच लाख बच्चों में से 40 हजार बच्चे यतीम हैं। इन बदनसीब बच्चों ने रोहिंग्या समुदाय के बर्बाद दमन के दैरान अपने माता-पिता ने जान से हाथ धोना पड़ा था। इनमें से ज्यादातर बच्चे जर्बर्दस्त उपोषण के शिकार हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि मौजूदा लालात में अभी तक एक लंबे समय तक रोहिंग्या मुसलमानों की अगस्त में लौटने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उन्हें अभी बांग्लादेश के शिविरों में रहना होगा। 90 के दशक में जो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पलायन कर गए थे, वे अभी भी शिविरों में रह रहे हैं और वापस जाना ही नहीं चाहते। यही हाल जौजूदा साड़े छह लाख रोहिंग्या मुसलमानों का है, जो गत अगस्त बाद पलायन करके बांग्लादेश आए हैं। इसलिए बांग्लादेश सरकार की इन शरणार्थियों को जीवन की बुनियादी सहालियतें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। विश्व बिरादरी की भी नेतृत्व के जिम्मेदारी है कि वे न केवल महिलाओं व लावारिस बच्चों के लिए जो इन शिविरों में रह रहे हैं बल्कि सबकी भरपूर दद करें और इनको भूख, बीमारी, हिंसा और महिलाओं को जिस्मफरीशी व मानव तस्करी से बचाए। म्यांमार में लौटने की नोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उन्हें अभी बांग्लादेश के शिविरों में रहना होगा। 90 के दशक में जो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पलायन कर गए थे, वे अभी भी शिविरों में रह रहे हैं और वापस जाना ही नहीं चाहते। साड़े छह लाख रोहिंग्या मुसलमानों का है, जो गत अगस्त के बाद पलायन करके बांग्लादेश आए हैं। बांग्लादेश सरकार की इन शरणार्थियों को जीवन की बुनियादी सहालियतें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। विश्व बिरादरी की भी नेतृत्व के जिम्मेदारी है कि वे न केवल महिलाओं व लावारिस बच्चों के लिए जो इन शिविरों में रह रहे हैं बल्कि सबकी भरपूर मदद करें और इनको भूख, बीमारी, हिंसा और महिलाओं को जिस्मफरीशी व मानव तस्करी से बचाए।

